बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 197 ● नई दिल्ली ● बुधवार 06 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

एक रुपये का भ्रष्टाचार न मिला: सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस बंद होने पर सिसोदिया की पहली टिप्पणी

नई दिल्ली । आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया आई है। जिसमें उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आठ साल तक जांच चली। लेकिन भ्रष्टाचार का एक रुपया भी बरामद नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि आठ साल तक जांच चली। सीबीआई-ईडी को रेड और मीडिया ट्रायल हुआ। यहां तक कि बच्चों के कपड़े तक खंगाले गए। लेकिन कोर्ट में खुद सीबीआई ने कहा कि एक रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं मिला। आगे लिखा कि तो जिन्होंने झूठा केस गढ़ा था।

उत्तराखंड के धराली में बादल फटा

पूरा गांव जमींदोज

30 सेकंड में सब तबाह.. 50 लोग लापता, 4 की मौत

लगातार तीन नालों में फटे बादल, हर्षिल हेलिपैड और आर्मी कैंप तबाह, आठ से 10 जवान लापता

नई दिल्ली ।

मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए और लोगों के घायल होने की आशंका बढ़ गई। बाढ़ के पानी की तेज लहरों ने घरों को निगल लिया और लोगों के चीखने-चिल्लाने के भयावह वीडियो ऑनलाइन सामने आए। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली के ऊंचाई वाले गांवों में बड़े पैमाने पर बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव अभियान के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय सेना को भी बचाव अभियान में शामिल किया गया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, मुझे उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना की सूचना मिली है.. हम लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया, खिर गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण धराली बाजार क्षेत्र में नुकसान हुआ है। हर्षिल से सेना की टुकड़ियों के साथ-साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भटवारी भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, धराली (उत्तरकाशी) में अचानक आई बाढ़ की घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। आईटीबीपी की तीन टीमें वहाँ भेजी गई हैं, और एनडीआरएफ की चार टीमें भी घटनास्थल पर भेजी गई हैं, जो जल्द ही पहुँचकर बचाव अभियान में लग जाएँगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके सुधांशु ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जान-माल के नुकसान की आशंका है। हमने एसडीआरएफ के साथ-साथ एनडीआरएफ को भी भेजा है और हम पहले आकलन कर रहे हैं और जैसे ही हमें नुकसान का सटीक पता चलेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पछता रहा होगा विपक्ष, एनडीए की संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (5 अगस्त) को एनडीए की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का सम्मान है और इसे देश के सामने लाना जरूरी है. प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष पर तंज भी कस दिया. पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करने के बाद विपक्ष खुद भी पछता रहा होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता कुछ भी बोलते हैं, इसकी वजह से उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ने लगी है. पीएम ने बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, वे कुछ भी बोलते रहते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया है. एनडीए की संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया. एनडीए संसदीय दल ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान दिखाए गए भारतीय सेना के साहस को सलाम किया. साथ ही, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई. प्रस्ताव में कहा गया, एनडीए संसदीय दल हमारे सशस्त्र बलों के साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया. उनका साहस हमारे राष्ट्र की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है. हम पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. पीएम मोदी ने तिरंगा अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों को घर-घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए कहा. इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (23 अगस्त) भी अपने क्षेत्रों में जाकर मनाने के लिए सांसदों को दिए निर्देश.

मुझसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि अभी 30-40 साल..., राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर क्यों भड़के नड्डा?

नई दिल्ली ।

राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मंगलवार को सदन के अंदर सीआईएसएफ कर्मियों की कथित तैनाती को लेकर तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सदन के वेल के पास सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया है। खड़गे ने कहा कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि कैसे सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया गया, जब सदस्य विरोध के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हमने कल और आज फिर ऐसा देखा। खड़गे ने सवाल किया कि क्या हमारी संसद इस स्तर तक गिर गई है? यह बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी निंदा करते है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे, तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब अरुण जेटली जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज जी लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, तो उन्होंने कहा था कि कार्यवाही में बाधा डालना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह हमारा अधिकार है। हालांकि, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खड़गे के दावों का खंडन किया और कहा कि यह सीआईएसएफ कर्मियों का नहीं, बल्कि संसदीय सुरक्षा का मामला था।

नई दिल्ली (साहिल गौड़)इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे, नेता विपक्ष श्री राहुल गाँधी के साथ इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे।

संसद सत्रः गोवा विधानसभा में एसटी को मिलेगा आरक्षण, लोकसभा में बिल पास

नई दिल्ली ।लोकसभा ने मंगलवार को गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया। इस दौरान विपक्ष बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध करता रहा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राय की विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच यह बिल ध्वनिमत से पास हो गया। आरक्षण को लेकर बिल में बताया गया है कि गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार काफी बढ़ी है। 2011 में गोवा की कुल आबादी 14,58,545 थी, जिसमें एससी की आबादी 25,449 और एसटी की आबादी 1,49,275 थी। इसके बावजूद, 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जबकि एससी के लिए एक सीट आरक्षित है। बता दें कि बिल का मकसद इस असमानता को दूर करना है ताकि एसटी समुदाय को भी संविधान में दिए गए आरक्षण का लाभ मिल सके। यह बिल पिछले साल यानी 6 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन अब जाकर पारित हुआ है। यह संसद के मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा द्वारा पारित किया गया पहला बिल है। बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल 30 जुलाई तक 48 यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। यानी अब ये यात्री किसी विमान में सफर नहीं कर सकते। नागरिक उड्डयन राय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। पिछले कुछ वर्षों में भी बड़ी संख्या में ऐसे यात्रियों को इस लिस्ट में डाला गया था, जहां 2024 में 82 और 2023 में 110 यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कार्रवाई विमान में अनुशासनहीन या हिंसक व्यवहार के कारण की जाती है।डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, तीन स्तर पर यात्रियों की बदसलूकी को वर्गीकृत किया जाता है।

इसमें लेवल कुछ प्रकार है कि लेवल एक में हल्का व्यवहार, जैसे जोर-जोर से बोलना। इसके लिए तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं दूसरे लेवल में शारीरिक या अपमानजनक व्यवहार। इसके तहत छह महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं अब बात अगर तीसरे लेवल की करें तो गंभीर हिंसा या खतरा होने के आधार पर कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि साल 2025 में जनवरी से जुलाई तक 6 बार विमान के इंजन बंद होने की घटनाएं और 3 बार मेडे कॉल की घटनाएं सामने आई हैं। ये जानकारी नागरिक उड्डयन राय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में दी। मंत्रालय ने बताया कि इंडिगो और स्पाइसजेट में दो-दो बार इंजन बंद हुआ। एयर इंडिया और एलायंस एयर में एक-एक बार ऐसी घटना हुई। जब किसी विमान को उड़ान के दौरान गंभीर खतरा होता है और तत्काल मदद चाहिए होती है, तो पायलट तीन बार मेडे, मेडे, मेडे कहकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है।

हर रोज चेन स्नैचिंग की 18 वारदातें! दिल्लीवालों को परेशान कर रहा क्राइम का यह आंकड़ा

नई दिल्ली । दिल्ली में चेन स्नैचिंग और लूट की वारदात से शहर वाले परेशान हो गए हैं. पुलिस का आंकड़ा बताता है कि औसतन दिल्ली में रोजाना लूट के 18 मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में दिल्ली के पॉश इलाके में, तमिलनाडु भवन के पास कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन चेन स्नैचिंग की वारदात का शिकार हो गईं. दूसरे मामले में, दिल्ली पुलिस ने एक स्नैचिंग गिरोह के चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका क्राइम करने का तरीका भी अनोखा था. बदमाश साधु बाबा का भेष धारण कर लोगों के पास आते थे, उनका भरोसा जीतते थे और फिर लूटपाट करते थे. यह गिरोह दिल्ली के मोती नगर इलाके में महिलाओं को निशाना बना रहा था. फिलहाल, इस गैंग का एक बदमाश अभी भी फरार है. पुलिस ने बताया कि ये लोग बाबा-महात्मा बनकर टैक्सी के पास आते थे और भीख मांगते समय उंगली से अंगूठी उड़ा देते थे. इस लूट की शिकार एक महिला के हाथ से उन्होंने सोने और हीरे की अंगूठी छीन ली थी. पुलिस को इस गिरोह के पास से 61 हीरे और पिघलाया गया सोना बरमाद हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों में एक विनोद कामत है जो ऑटो उपलब्ध कराता था, दूसरा गुरचरण सिंह है जो सोने की अंगूठी खरीद कर उसे पिघलाता था. तीसरा कबीर और चौथा बिरजू है. तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद सुधा रामाकृष्णन सोमवार (4 अगस्त) को मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, जब स्कूटी सवार एक बदमाश ने उनके गले से चेन छीन ली. इस संघर्ष में सांसद को भी कई चोटें आईं. उन्होंने खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई और सख्त एक्शन के निर्देश देने की अपील की.

आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली । दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार अनिवार्य होगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की पात्रता निर्धारित करता है. इस कदम का उद्देश्य धांधली और अनियमितताओं को रोकना है. केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. योजना से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करता है. उपराज्यपाल ने %आय प्रमाण पत्र जारी करने% की सेवा को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस धारा के तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार-आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर सकती है, ताकि भारत के संचित निधि या राज्य के संचित निधि से खर्च होने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त की जा सके. आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के

छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पेंशन, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता आदि. राजस्व विभाग ने कहा कि सेवाओं, लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए आधार को पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग करने से सेवा वितरण की प्रक्रिया आसान होती है और पारदर्शिता बढ़ती है. इससे लाभार्थियों को उनके हक का लाभ सीधे, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से मिलता है. इसके अलावा, आधार सत्यापन से पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है. यूआईडीएआई, भारत सरकार ने 25.11.2019 के एक परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकारों को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य करने का अधिकार दिया था, यदि योजनाएं राज्य के संचित निधि से वित्त पोषित हों. अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर नहीं रखता है और योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा. यदि व्यक्ति/लाभार्थी नाबालिग है और उसके पास आधार नंबर नहीं है, तो वह आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची के साथ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता का नाम हो और स्कूल के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो, दे सकता है. अन्य सभी लाभार्थी (बच्चों को छोड़कर), जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आधार नामांकन पहचान पर्ची के साथ बैंक या डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, या ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत कर सकते हैं. उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को यह सलाह भी दी है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों को इन योजनाओं के लिए आधार की आवश्यकताओं की जानकारी हो और यह सुनिश्चित हो कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न होना पड़े.

पीएम व केंद्रीय गृहमंत्री अचानक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की- राजनीतिक गलियारों में सियासी अटकलें चरम पर पहुंची!

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की नजरें भारत की हर गतिविधियों पर लगी रहती है वैसे भी अभी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चल रहा है तो निगाहें और भी पैनी हो जाती है कि, संसद किस तरह के बड़े फैसले लेता है,या फिर ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटों की बहस के बाद अब फ़िर एसआईं आर पर संसद में हंगामें केकारण कामकाज ठप्प पड़ा है,ऊपर से उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होने की घोषणा हो चुकी है सांसद में बड़े-बड़े बिल पेंडिंग है, इस बीच भारत सरकार व पार्टी के दो मुख्य पावरफुल सर्वोच्च दिग्गजों का अचानक रविवार 3 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की गतिविधि ने भारत ही नहीं पूरे विश्व का ध्यान खींचा है,इसीलिए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि जरूर कोई अति खास महत्त्वपूर्ण मुद्दा होगा जो दोनों दिग्गज अलग-अलग रूप से राष्ट्रपति भवन में जाकर उनसे मुलाकात की है,जिसका खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा, परंतु राजनीतिक हल्कों में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, विपक्ष अलर्ट हो गया है कि कहीं कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया जा रहा है, या फिर मानसून सत्र में कोई बड़ा बिल तो पेश नहीं किया जाएगा और हंगामें के बीच ध्वनिमत से पारित कर लिया जाएगा या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी तैयारी या फिर उपराष्ट्रपति के नाम पर मोहर लग चुकी है इसके कयास लगाए जा रहे है। चूंकि सरकार के दो मुख्य स्तंभों का मानसून सत्र में राष्ट्रपति से मिलना कोई बड़ा फैसला, बड़ा बिल, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला हो सकता है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे पीएम गृहमंत्री ने अचानक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की, राजनीतिक गतिविधियों में सियासी अटकलें चरम सीमा पर पहुंची। साथियों बात अगर हम रविवार 3 अगस्त 2025 को भारत में सियासी हलचल तेज होने की करें तो,रविवार को पीएम ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आया है कि पीएम और गृहमंत्री के राष्ट्रपति से मिलने के पीछे क्या कारण है। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की सियासी दरअसल, दोनों नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार या तो कोई बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है या फिर सदन में कोई बड़ा बिल लाना चाहती है। इसलिए दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। इन दोनों मांगों को लेकर विपक्ष ने लगातार प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग के बाद संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई है,लेकिन एसआईं आर पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहता है लेकिन सरकार अभी तक इसपर बिल्कुल ही तैयार नहीं है। साथियों बात अगर हम इस मुलाकात के माइनें 9 सितंबर 2025 को होने वाले चुनाव से जोड़कर देखें तो, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 9 सितंबर को मतदान होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। 7 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में फिर से उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होना है। यहां समझें दोनों सदनों का नंबर गेम, संसद की दोनों सदनों में सांसदों की कुल संख्या 782 है। उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता होती है। लोकसभा में 542 सदस्यों में, एनडीए के 293 सांसद हैं। वहीं, राज्यसभा में 240 सदस्यों में से 129 सदस्य एनडीए के हैं। कुल मिलाकर एनडीए को 422 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में एनडीए का उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है।

फिलहाल की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। यहां रेखांकित करने वाली बात यह है कि पार्टी के पास इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ और नायडू जैसी स्थिति नहीं है अभी तीन पहियों पर सरकार सवार है इसलिए बाकी दो पहियों से उम्मीदवार के नाम पर सहमति लेना जरूरी हो गया है,नहीं तो नंबर गेम में बड़ा खेला होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता नंबर गेम के हिसाब से और दो पहिए अगर क्रॉस वोटिंग कर गए गए तो हो सकता है उपराष्ट्रपति विपक्ष का हो जाए पर इसकी संभावना बहुत कम है। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान की करें तो, जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से पूछा गया कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि केवल सत्तारूढ़ पार्टी का उम्मीदवार इस पद पर बैठ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह किसे उपराष्ट्रपति बनाएगी। थरूर ने कहा कि हम बस इतना जानते है कि वह जिसे उम्मीदवार बनाएगी, वह व्यक्ति ही अगला उपराष्ट्रपति होगा। यह संसद के दोनों सदनों का चुनाव है।उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभाएं भी चुनाव करती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा ही मतदान करते है। इसलिए हम बहुमत पहले से ही जानते है। आगे कहा कि इतना समझ लीजिये कि अगला उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल द्वारा नामित व्यक्ति होगा।उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र अगले उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए विपक्ष की भी सलाह लेगा, लेकिन कौन जाने? साथियों बात अगर हम उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया व योग्यता की करें तो, उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया और योग्यता (1) भारत का नागरिक होना चाहिए(2) कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए (3) राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए (4) उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया होती है (5) उम्मीदवार को 15,000 रूपए की जमानत राशि जमा करनी होती है (6) 1/6 वोट न मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है (7) नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है।

(8) मतदान प्रक्रिया में, मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते है (9) उदाहरण के लिए, यदि तीन उम्मीदवार, B. और C हैं, तो मतदाता प्राथमिकता दर्शा सकता है (10) हर सांसद एक वोट देता है (11) प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को 1, 2, 3 के क्रम में दर्शाता है (12) मतों की गिनती के बाद, उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार मतों का आवंटन किया जाता है (13) सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है. अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पीएम व केंद्रीय गृहमंत्री अचानक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की- राजनीतिक गलियारों में सियासी अटकलें चरम पर पहुंची।सरकार के दो मुख्य स्तंभों का मानसून सत्र में राष्ट्रपति से मिलना कोई बड़ा फैसला,बड़ा बिल,जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव का मामला सरकार के दो सर्वोच्च दिग्गजों का राष्ट्रपति से एक ही दिन अलग-अलग मिलना, किसी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा करता है।

टैरिफ दादागिरी के बीच 'स्वदेशी' एक जनक्रांति बने

वाराणसी में अपने लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे संकल्प लें कि अपने घर स्वदेशी सामान ही लाएंगे। उनका यह आह्वान न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'दबाव की राजनीति' और 'टैरिफ की दादागिरी' का माकूल जवाब है बल्कि भारत को सशक्त अर्थ-व्यवस्था बनाने की बुनियाद भी है। मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान इसी सोच के साथ किया है। उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत को 'लोकल के लिए वोकल' बनना होगा। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक गहन आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीति है जो हमें बाहरी निर्भरता से मुक्त कर सकती है। यह वही आत्मनिर्भरता है, जिसका बीजारोपण महात्मा गांधी ने चरखे और खादी के माध्यम से किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी जागरण के माध्यम से कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का ही परिणाम है कि उन्होंने दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत की अर्थव्यवस्था को 'मृत अर्थव्यवस्था तक कह दिया, उनका यह कहना न केवल तथ्यहीन और निराधार है, बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता पर एक असभ्य एवं अक्षम्य आक्षेप भी है। इससे भी अधिक विडम्बनापूर्ण और चिंताजनक बात यह है कि भारत के कुछ विपक्षी दलों ने इस अपमानजनक बयान को घरेलू राजनीति को 'ऑक्सीजन' मानकर इसे आंतरिक राजनीति का हथियार बनाकर न केवल प्रचारित किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन भी किया। अक्सर विपक्षी दल देशविरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने में जुट जाते है। वे यह भूल जाते है कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का अंग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात के समय एकजुटता ही राष्ट्रवाद की पहचान होती है। यह वही देशविरोधी मानसिकता है जो विदेशी मंचों पर देश की छवि को चोट पहुंचाती है और राजनीतिक स्वार्थों एवं मतभेदों को राष्ट्रीय स्वाभिमान से ऊपर रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह ट्रंप ने 'मृतप्राय' कहा, वह न केवल मौजूदा आर्थिक तथ्यों की अवहेलना है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दबाने का एक रणनीतिक षड्यंत्र भी है। आईएमएफ, विश्व बैंक और ओईसीडी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी लगातार यह संकेत देती रही हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद जिस गति से पुनरुत्थान किया है, वह अनेक विकसित देशों के लिए भी उदाहरण है। सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था न तो मृत है, न ही दिशाहीन। हां, चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आय असमानता, लेकिन इनसे जूझते हुए भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत की वाणी अब कमजोर नहीं, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। ऐसे समय में जब अमेरिका जैसे देश एकतरफा फैसलों से वैश्विक व्यापार संतुलन को तोड़ने पर आमादा हैं, तब भारत को अपनी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मंत्र को एक संकल्प बनाकर व्यवहार में लाना होगा। अमेरिका हो या चीन, आर्थिक नीतियों में नैतिकता नहीं, स्वार्थ ही केंद्र में रहता है। इसीलिए भारत को अब यह समझना होगा कि केवल आयात पर निर्भर रहकर हम अपनी आर्थिक सुरक्षा नहीं कर सकते। जब तक हम उत्पादन, निर्माण और उपभोग के क्षेत्र में स्वदेशी विकल्प नहीं अपनाते, तब तक हम इस टैरिफ आतंकवाद और वैश्विक अस्थिरता के शिकार बने रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से यह बात दोहराते रहे हैं कि भारत की आर्थिक समृद्धि का मूल मंत्र 'स्वदेशी' है। यह विचार केवल देसी वस्तुओं के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है, स्वदेशी संसाधनों, तकनीकों, कौशल और संस्कृति के आधार पर विकास का रास्ता तय करना। भारत का आर्थिक इतिहास इसका साक्षी है कि जब-जब देश ने अपनी आंतरिक क्षमताओं पर विश्वास किया, तब-तब उसने वैश्विक मंच पर अपना प्रभुत्व सिद्ध किया। चाहे दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो, अंतरिक्ष में इसरो की सफलताएं हों या कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन बनाना, भारत ने दिखाया है कि वह किसी से कम नहीं। स्वदेशी का मंत्र सिर्फ 'यहां बनाएं' तक सीमित नहीं है, यह 'यहां के लोगों द्वारा, यहां की सोच के साथ' बनाया गया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी का 'मेक इन इंडिया' अभियान अब 'मेड बाय इंडिया' की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत को ऐसी आर्थिक संरचना बनानी होगी जिसमें विदेशी पूंजी या तकनीक की बजाय स्वदेशी नवाचार, स्वदेशी उद्योग, और स्वदेशी उद्यमिता को बल मिले। इस संदर्भ में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जो नीतियां बनें, वे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हों, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लॉबी के दबाव में चलने वालीं। आज का समय वैसा ही है जैसा 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय था, जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। आज फिर एक नई क्रांति की जरूरत है, लेकिन यह क्रांति फैक्ट्रियों में, बाजारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाएगी। हमारे युवाओं को चाहिए कि वे स्टार्टअप, इनोवेशन और तकनीकी प्रयोगों में विदेशी नकल न करें, बल्कि भारतीय ज़रूरतों और मूल्यों के अनुरूप नए समाधान विकसित करें। यही आत्मनिर्भर भारत की आत्मा है। हर भारतीय को यह समझना होगा कि जब वह विदेशी मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, या चीनी उत्पाद खरीदता है, तो वह सिर्फ एक उत्पाद नहीं ले रहा, बल्कि वह अपने देश के एक कारीगर, किसान या उद्यमी से रोज़ी-रोटी छीन रहा है। अब समय है कि उपभोक्ता भी जिम्मेदार बनें। स्वदेशी उपभोग सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देशभक्ति का आधुनिक रूप है। आज जब वैश्विक पूंजीवाद लड़खड़ा रहा है और पश्चिमी देशों की नीतियों में आत्मकेंद्रितता हावी हो रही है, भारत को अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और बौद्धिक जड़ों की ओर लौटना ही होगा। यही समय है जब 'स्वदेशी' एक आंदोलन बने, एक जनक्रांति बने और एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था की नींव डाले जो टिकाऊ, समावेशी और पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वदेशी का दीप जलाया है, वह केवल सरकार का काम नहीं, यह हम सभी का नैतिक, राष्ट्रीय और आत्मिक दायित्व है।

भारत से इतने खफा क्यों हो गए ट्रम्प

इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प भारत के पक्के दोस्त हुआ करते थे। अभी भी वो भारत को अपना दोस्त ही बताते है, वे भारत से इतने खफा क्यों हो गए कि टैरिफ का बड़ा बोझ डाल दिया और पाकिस्तान को ऐसे गोद में लेकर बैठ गए जैसे भारत से उन्हें कोई रिश्ता ही न रखना हो। हमें इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए। मैं अमेरिका के सामने झुकने की बात नहीं करता लेकिन हमारी कूटनीति के समक्ष इस वक्त बड़ी चुनौती है। भारत को यह समझना होगा कि ट्रम्प आखिर चाह क्या रहे हैं? हम भारतीयों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के साथ भारत की जंग उन्होंने रुकवाई लेकिन उन्हें पता था। भारत ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ना, बेचारे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके पास पैट्रोलियम पदार्थों का ऐसा अकूत भंडार है कि वे किसी दिन भारत को भी तेल बेचने की क्षमता रखते हैं। वह तो उन्हें तब पता चला जब ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी दी कि पाकिस्तान के पास तेल का विशाल भंडार है। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। जो पाकिस्तानी पैट्रोल और डीजल की कमी से जूझ रहे है, जिनके यहां पिछले दिनों तेल उत्पादन में 11 प्रतिशत की कमी आई है, उन्हें यदि मुंगेरीलाल का यह हसीन सपना दिखा दिया जाए कि वह तो अरब देशों की तरह तेल बेचने वाले बन जाएंगे तो क्या हालत होगी? वो देश पगलाएगा कि नहीं? अब जो थोड़ा पढ़े-लिखे हैं या जिन्हें पैट्रोलियम भंडारों के बारे में चल रही खोजबीन की जानकारी है, वे जानते हैं कि हालात क्या है। भारत के पास कच्चे तेल का प्रामाणिक भंडार 5600 लाख बैरल के आसपास है जबकि पाकिस्तान का भंडार महज 236 लाख बैरल के आसपास ही है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे बताते हैं कि फरवरी 2025 में भारत में प्रतिदिन 6 लाख बैरल तेल का उत्पादन हुआ जबकि पाकिस्तान में उसी महीने यह मात्रा केवल 68 हजार बैरल थी। हां, समय-समय पर यह जरूर कहा जाता रहा है कि पाक के पास तेल का बड़ा भंडार हो सकता है। 2015 में अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने बगैर किसी खोज के केवल विश्लेषण के आधार पर कह दिया था कि पाकिस्तान में लगभग 9 अरब बैरल तेल भंडार हो सकता है। आश्चर्यजनक रूप से भारत का आंकड़ा केवल 3.8 अरब बैरल ही आंका गया था। उस वक्त भी अमेरिका की नीयत पर शंका उत्पन्न हुई थी लेकिन बहुत हल्ला नहीं मचा क्योंकि कुछ भी प्रामाणिक नहीं था लेकिन असली सवाल है कि वे संदेश क्या देना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से ट्रम्प भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल निकालने का काम अमेरिकी कंपनियां करेंगी और पाकिस्तान को मालामाल कर देंगी। किसी देश को डराने का यह कौन सा तरीका है? क्या ट्रम्प यह मान कर चल रहे थे कि अमेरिका जिन गायों को तंदुरुस्त रखने के लिए मांस से बना आहार देता है, उसका दूध वे धींगा-मुश्ती से भारत में बेच लेंगे। मगर वे भारत की संस्कृति को नहीं जानते। हमारे यहां सरकार किसी भी दल की हो, ट्रम्प का सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। हम खूनी दूध नहीं पीते। इसीलिए हमारी सरकार नहीं झुकेगी। संस्कृति का बहुत बड़ा फर्क है जनाब!

सम्पादकीय...

पश्चिम के आगे झुकने का युग समाप्त, ट्रंप की धमकी पर भारी पड़ेगी मोदी की कूटनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जटिल कूटनीतिक और राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे है। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी को मजबूती से बनाए रखना चाहते है। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक संदेश भी है कि पश्चिम के सामने झुकने का युग अब समाप्त हो चुका है। देखा जाये तो मोदी सरकार वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बनकर उभरी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और नैतिक उपदेशों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने हितों को स्वतंत्र रूप से साधने की नीति अपनाई। यह वही रणनीतिक स्वायत्तता है, जिसकी बात भारत दशकों से करता आया है, पर जिसे आज व्यवहार में लाने का साहस शायद पहली बार किसी सरकार ने इस हद तक दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनौती केवल बाहरी नहीं है। देश के भीतर कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निकटता पर तंज कस रहे हैं। माई फ्रेंड डोनाल्ड जैसे वाक्य अब राजनीतिक व्यंग्य बन चुके हैं। कांग्रेस यह सवाल उठा रही है कि अगर अमेरिका से घनिष्ठता इतनी ही प्रभावशाली थी, तो भारत को टैरिफ धमकी क्यों झेलनी पड़ रही है? देखा जाये तो यह आलोचना राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है, पर इसमें कूटनीतिक यथार्थ की गहराई को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत आज आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से एक उभरती शक्ति है और ऐसे में विश्व के साथ उसकी मोल-भाव करने की शैली भी बदली है। मोदी जिस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह न केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि विकल्पों का निर्माण भी कर रहा है– जैसे BRICS+ का मंच, ऊर्जा विविधता की दिशा में कदम और नए व्यापारिक सहयोग। इसके अलावा, मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इस समय एक परीक्षण की कसौटी बन चुका है। प्रधानमंत्री को अब यह साबित करना है कि वह पश्चिम के दबाव को संतुलित करते हुए, रूस से रिश्ते बनाए रखते हुए और विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता के रूप में उभार सकते है। देखा जाये तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोदी को तीन स्तरों पर निर्णायक पहल करनी होगी- 1. अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए, ट्रेड वार को टालना होगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्पष्ट पैरवी करनी होगी। 2. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि आयात और शुल्क जैसे हथियारों का असर सीमित हो और ऊर्जा आपूर्ति में विविधता भी लानी होगी। 3. आंतरिक एकता और विपक्ष के प्रहारों का उत्तर तथ्यों और नीतिगत पारदर्शिता से देना होगा, ताकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि दिखाई दे। देखा जाये तो यह वह घड़ी है जब प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व के अपने सबसे कठिन अध्याय में प्रवेश करना पड़ा है। लेकिन यदि वे इस दौर को सफलता से पार कर जाते हैं, तो यह केवल उनकी नहीं, बल्कि एक नए भारत की विजय होगी– जो दबाव में नहीं झुकता, हितों की रक्षा करता है और दुनिया को सम्मान के साथ संवाद करना सिखाता है। और तब शायद 'मोदी है तो मुमकिन है' सिर्फ चुनावी नारा नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ भी बन जाएगा। जहां तक ताजा घटनाक्रमों की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये गए वक्तव्य में साफ तौर पर कहा गया है कि रूस से आयात ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता को बनाये रखने के लिए उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने यह भी उजागर किया है कि अमेरिका और यूरोप स्वयं अभी भी रूस से उर्वरक, खनिज, रसायन, यूरेनियम और एलएनजी जैसी सामग्रियों का भारी व्यापार कर रहे हैं। भारत का यह तर्क एकदम सही है कि जब तक अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त नहीं करते, तब तक भारत को नैतिकता के कठघरे में खड़ा करना न केवल दोहरा मापदंड है, बल्कि 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' भी। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर शुल्क बढ़ाने और रूसी तेल की खरीद पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी को विशेषज्ञ अमेरिका की घरेलू राजनीति और आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊँचे दामों में बेचकर लाभ कमा रहा है, साथ ही यूक्रेन युद्ध में नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। किंतु यह आरोप राजनीतिक बयानबाज़ी अधिक लगता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पुनः बिक्री और रिफाइनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कई देश अपनाते हैं। देखा जाये तो ट्रंप द्वारा शुल्क बढ़ाने की घोषणा एक तरफ भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर इसे अमेरिका के कृषि और डेयरी उद्योग के समर्थन में लॉबिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं, रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की 'नव-उपनिवेशवादी' नीति का उदाहरण बताया है। क्रेमलिन का यह दावा कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ पर आर्थिक दबाव बना रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अमेरिका की एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। बहरहाल, भारत जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता आया है, उसका असली परीक्षण ऐसे ही समय में होता है जब उसे पश्चिमी दबावों, वैश्विक व्यापारिक हितों और घरेलू राजनीतिक आलोचनाओं के बीच संतुलन साधना हो। अमेरिका और यूरोपीय देशों को समझना होगा कि रूस से तेल खरीद केवल व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक विदेश नीति का प्रतीक भी है।

सीएम योगी की दिल्ली यात्रा

पिछले दिनों यूपी सीएम योगी दिल्ली में थे और वह उस दौरान कई बड़े नेताओं से मिले। एक बड़े नेता ने योगी से कहा कि आप यूपी के दबंग ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह से न उलझा करें', भाजपा के इस नेता का मानना था कि बृजभूषण सिंह का गोंडा व उससे सटे दो-तीन जिलों में खासा प्रभाव है। सो, आने वाले चुनाव में वे इन जिलों में भाजपा का खेल बिगाड़ सकते है, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा न छेड़ा जाए। इस पर योगी ने उनको बैलेंस करने के लिए मनकापुर के राजा कीर्तिवर्द्धन सिंह का नाम लिया और कहा कि बृजभूषण शरण की काट के तौर पर हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर नेता ने तत्परता से कहा हमने कीर्तिवर्द्धन सिंह को दिल्ली में पहले से राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी हुई है, पर क्या आपको लगता है कि इन दोनों लोगों की ताकत में कोई मेल है' कहते हैं इसके बाद ही योगी बृजभूषण से अकेले में मिलने को राजी हो गए, इन दोनों नेताओं के बीच 2023 के बाद से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी, पर इस बार योगी अपने इस सजातीय ठाकुर नेता से जी खोल कर मिले, और इनके बीच कोई डेढ़ घंटे की अहम बातचीत हुई जो रिश्तों के दरम्यान जम आई बर्फ को पिघलाने के लिए काफी मानी जा सकती है। इसके बाद नेता ने योगी को एक और अहम नसीहत देते हुए कहा कि आपको समय-समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से भी बात करते रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि वे न तो आप जितने बड़े 'मास लीडर' हैं और न ही इतने ही करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी, फिर भी उनकी सहजता ही उन्हें राजनीति में इतना आगे लेकर आई है। एक तो वे सबको साथ लेकर चलने में भरोसा रखते हैं, दूसरा उनमें राजकाज चलाने की प्रशासनिक दक्षता कूट-कूट कर भरी है। योगी ये सूक्त ज्ञान लेकर वापिस लखनऊ लौट आए, केंद्र के साथ एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने का वचन देकर। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी पिछले दिनों यहां के प्रदेश अध्यक्ष हमिद कर्रा ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, 'हमारी रियासत, हमारा हक' मूवमेंट की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कैडर, अपने जिलाध्यक्षों और अन्य पार्टी नेताओं को मीडिया से दूरी बना कर रखने की ताकीद दी है। कर्रा ने अपने नेताओं को बेहद साफ-साफ हिदायत दी है कि 'पार्टी का कोई भी नेता न तो सोशल मीडिया में, न अखबारों में और न ही टीवी डिबेट में बोलेगा, ना हिस्सा लेगा।' कर्रा ने पार्टी नेताओं से मीडिया से दूरी बना कर रखने को कहा है। दरअसल, कर्रा का यह फैसला दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद आया है, जहां प्रदेश प्रभारी सईद नासिर हुसैन ने कर्रा विरोधी नेताओं को जानबूझ कर मंच पर जगह दे दी थी, इसके विरोधस्वरूप कर्रा ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस का यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया था कि 'उनकी तबियत ठीक नहीं है।' कर्रा व नासिर हुसैन की यह जंग आने वाले दिनों में और खुल कर सामने आ सकती है। कांग्रेस के चंडीगढ़ के सांसद व पार्टी के तेजतर्रार नेता मनीष तिवारी अपने हाईकमान के ताजातरीन फैसलों से आहत नज़र आते हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोलने के लिए जब कांग्रेस ने अपने वक्ताओं की सूची जारी की तो उसमें से तिवारी का नाम नदारद था।

हाईकमान का यह फैसला किंचित चौंकाने वाला जरूर था, क्योंकि पेशे से वकील मनीष तिवारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार हैं और वे गौरव गोगोई जैसों की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार वक्ता भी हैं। पर तिवारी उसी वक्त से अपने हाईकमान की आंखों की किरकिरी बन गए जब पीएम मोदी ने बड़ी चतुराई से 59 नेताओं व राजनयिकों की टीम में इनका नाम भी शामिल कर लिया था, बिना कांग्रेसी हाईकमान से पूछे। जो 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर गए थे। इसी सूची में शशि थरूर व सुप्रिया सूले जैसे नेताओं के नाम भी शामिल थे। सनद रहे कि कैसे सुप्रिया सूले ने इस दफे 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोलते हुए मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। कांग्रेस हाईकमान को अंदेशा था कि थरूर व तिवारी जैसे लोग भी इसी परिपाटी का अनुसरण करेंगे सो उन्हें कांग्रेस ने अपनी वक्ताओं की सूची में रखा ही नहीं। इससे आहत होकर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट डाला- 'भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।' जिस दिन प्रियंका गांधी को सदन में बोलना था, मनीष उस रोज प्रियंका से मिले और उनको पहले ही सूचित कर दिया कि 'वे एक कांफ्रेंस के लिए दो दिनों के लिए आज शाम ही लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, सो, वे सदन में उपस्थित नहीं रह पाएंगे।' इसके बाद ही मनीष ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो ओडिशा भाजपा के 17 असंतुष्ट विधायकों ने दिल्ली आकर यहां अपना डेरा-डंडा जमाया हुआ था। विधायकों के इस ग्रुप ने दिल्ली में भाजपा के कई सीनियर नेताओं से मिल कर उनके समक्ष अपनी गुहार लगाई। सूत्र बताते हैं कि ये विधायक गण ओडिशा के भाजपा राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, संगठन प्रभारी सुनील बंसल और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष से मिले। इन विधायकों की शिकायत है कि पूरा राज्य ही नौकरशाहों की गिरफ्त में है, राज्य के मुख्यमंत्री मांझी की अनुभवहीनता का लाभ उठा कर नौकरशाहों ने पूरी सरकार ही जैसे 'टेकओवर' कर ली है, अगर हालात यूं ही बने रहे तो फिर राज्य में अगली दफा बीजू जनता दल को आने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल, ये असंतुष्ट विधायक मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की जगह राज्य की बागडोर डिप्टी सीएम कनक वर्द्धन सिंह देव को सौंपने की वकालत कर रहे हैं।

समझा जाता है कि भाजपा शीर्ष की ओर से इन विधायकों को यह आश्वासन मिला है कि 'अभी आप वापिस जाइए, दिल्ली में नई व्यवस्था लागू होने तक यानी नया अध्यक्ष आने तक इंतजार कीजिए।' अब इन विधायकों का दर्द है कि पिछले 7 महीने में वे तीन बार अपनी गुहार लेकर दिल्ली आ चुके हैं, हर बार उनसे यही कहा जाता है कि 'दिल्ली में नई व्यवस्था लागू होने तक इंतजार कीजिए, जब पार्टी इतने दिनों में अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है तो हमारे भाग्य का क्या फैसला करेगी' उत्तराखंड भाजपा में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ इनके पूर्ववर्ती सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुल कर मोर्चा खोल दिया है। रावत धामी विरोधी विधायकों व नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पर इन दिनों रावत ने किंचित स्वर बदल लिए हैं, अब वे अगले सीएम के तौर पर अपना नाम आगे नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जगह अनिल बलूनी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। रावत जानते हैं कि उनके खिलाफ पहले से भ्रष्टाचार के कई मुकदमें चल रहे हैं अगर इसमें से एक में भी दोष सिद्ध हो जाए तो उनका सीएम बनना खटाई में पड़ सकता है, शायद इसीलिए अब वे अपनी जगह बलूनी पर सारा दांव लगा रहे हैं। पर उनकी एकमात्र मुश्किल यह है कि वे जमीनी नेताओं में शुमार नहीं किए जाते। इस बार का चुनाव भी वे मुश्किल जीत पाए हैं। उनके लिए दूसरी बड़ी समस्या है कि प्रदेश में 40 फीसदी राजपूतों की आबादी है, सो अगर एक राजपूत सीएम (धामी) को हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह एक ब्राह्मण (बलूनी) को कैसे राज्य की कमान सौंपी जा सकती है जिस रोज सदन में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर प्रियंका व राहुल गांधी को बोलना था, उस रोज प्रियंका गांधी अपने भाषण से पहले काफी देर तक अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कमरे में बैठी रहीं।

दोनों भाई-बहन के दरम्यान इस बात पर गंभीरता से मनन हुआ कि 'इस मुद्दे पर कौन क्या बोलेगा।' फिर राहुल ने प्रियंका से कहा कि 'आप 'ऑपरेशन सिंदूर' के भावनात्मक पहलुओं को उकेरना, और मैं इस ऑपरेशन पर सरकार की गलतियों पर बिंदुवार बोलूंगा। आपके स्पीच की टोन भावनात्मक कनेक्ट वाला रहेगी और मैं विषय वस्तु पर फोकस करूंगा।' भाई-बहन की इसी रणनीति के दीदार संसद में भी हुए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घावते ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साव पैन्तलक्ष्मा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घावते, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN2019[illegible])

भारत-फिलीपींस रिश्तों का नया दौर: राष्ट्रपति मार्कोस बोले- आतंकवाद के खिलाफ साथ, रणनीतिक साझेदारी करेंगे मजबूत

नई दिल्ली ।

भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारत के साथ साझा मूल्यों और रणनीतिक साझेदारी को लेकर भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ एकजुटता का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जताया। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने कहा कि मैं भारत को पहलगाम हमले में हुई दुखद घटना को लेकर हमारी एकजुटता का संदेश देता हूं और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी भारत के साथ हूं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, मैं भारत को विकसित भारत 2047 के सपने की ओर मजबूती से आगे बढ़ते देखने पर बधाई देता हूं। यह सब पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व में हो रहा है। मार्कोस जूनियर ने आगे कहा कि दिल्ली पहुंचते ही उन्हें भारत में हो रहे तेज बदलाव और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा का अहसास हुआ। उन्होंने भारत की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं भारत में हूं। मेरे चार पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने भी भारत की यात्रा की थी, जिनमें मेरे पिता भी शामिल थे, जो 1976 में भारत आने वाले पहले

फिलीपींस राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही राष्ट्रपति मार्कोस ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आपने और भारत सरकार ने मुझे, मेरी पत्नी और हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल को जिस गर्मजोशी और सम्मान से स्वागत किया, उसके लिए दिल से आभार। साथ ही, हमारे लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध से छूट देने के लिए भी धन्यवाद। अंत में राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि भारत और फिलीपींस के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। -मैं बहुत खुश हूं कि आज हमने इस दोस्ती को और आगे बढ़ाते हुए इसे पूर्ण रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और फिलीपींस साझा मूल्य, हित और चिंताएं रखते हैं, खासकर वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितियों के बीच, जो दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालती हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली में एक खास कार्यक्रम के दौरान मिलकर स्मारक डाक टिकट जारी किए। यह डाक टिकट भारत और फिलीपींस के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों को दर्शाते हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को यादगार बनाने के लिए इन टिकटों को जारी किया गया है। इसके साथ ही इस मौके पर दोनों नेताओं ने आपसी दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इसके साथ ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्देज मार्कोस जूनियर की मौजूदगी में भारत और फिलीपींस के बीच कई समझौतों (एमओयूएस) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाना है। यह समझौते व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।

सुल्तानपुरी में बोरवेल सीलिंग की कार्रवाई- selective कार्रवाई या एनजीटी निर्देशों का पालन?

नई दिल्ली (ए के चौधरी) सुल्तानपुरी-बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में आज रोहिणी सब-डिवीजन प्रशासन की ओर से अवैध बोरवेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के मानदंडों का उल्लंघन करने पर बी-4/492 और बी-2/288, सुल्तानपुरी के बोरवेलों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई क्षेत्र में जलस्रोतों के अनियमित दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन को रोकने के तहत की गई बताई जा रही है।

हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में रोष भी देखने को मिला। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह कार्रवाई -चिंहित और एकतरफा- लग रही है। स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्रीय नेताओं के इशारे पर चुनिंदा बोरवेलों को ही निशाना बनाया गया, जबकि सुल्तानपुरी के सी-ब्लॉक मछली मार्केट सहित कई स्थानों पर दर्जनों अवैध बोरवेल आज भी चालू हैं।

बदले की कार्रवाई?

स्थानीय दुकानदार और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन यदि वास्तव में एनजीटी के दिशा-निर्देशों को लेकर गंभीर है, तो पूरे सुल्तानपुरी में एक समान कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सी-ब्लॉक की मछली मंडी, जो वर्षों से दर्जनों अवैध बोरवेल का केंद्र बनी हुई है, वहां अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कानून सबके लिए समान क्यों नहीं?

एनजीटी द्वारा भूजल संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश हैं कि बिना लाइसेंस या अनुमति के बोरवेल चलाना गैरकानूनी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब पूरे क्षेत्र में अवैध बोरवेल खुलेआम चल रहे हैं, तो कार्रवाई केवल दो-तीन स्थानों पर ही क्यों?

जनता का सवाल प्रशासन से-

क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष है?

क्या सी-ब्लॉक मछली मार्केट में शिकायतों के बावजूद प्रशासन आंख मूंदे बैठा है?

क्षेत्रीय निवासियों की मांग-

सभी अवैध बोरवेलों पर निष्पक्ष और एकसमान कार्रवाई हो।

प्रशासन को चाहिए कि वह पूरे क्षेत्र में अभियान चलाकर हर अवैध बोरवेल को चिन्हित करे और उस पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि आम जनता का कानून पर भरोसा बना रहे और पर्यावरण संतुलन की रक्षा हो सके।

टीबी रोगियों हेतु नया अभियान, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी विभाग और संस्थान टीबी जागरूकता और उन्मूलन गतिविधियों में होंगे शामिल

चण्डीगढ़ ।

भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना

यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों और संस्थानों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी दिशा में, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों और संस्थानों ने टीबी जागरूकता और उन्मूलन की गतिविधियों में भाग लेना जरूरी है, इसी सन्दर्भ में हरियाणा ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी विभागों और संस्थानों में टीबी जागरूकता और उन्मूलन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नया अभियान शुरू किया है। यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत हरियाणा राज्य टीबी सेल की एक टीम ने पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल और पार्षदों से मुलाकात की। टीम में जिला टीबी अधिकारी, पंचकूला डॉ. संदीप ढाबड़ा, डब्ल्यूएचओ सलाहकार डॉ. सुखवंत सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉ. शरणजोत सिंह और जिला कार्यक्रम समन्वयक सुश्री ललिता शामिल थी। उन्होंने सभी को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बताया और समझाया कि टीबी मुक्त भारत के लिए शहरी कार्य मंत्रालय कैसे सहयोग कर सकता है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से टीबी मुक्त भारत अभियान को एक नई गति मिलेगी। यह साझेदारी टीबी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि टीबी की रोकथाम के लिए शहरी मलिन बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और टीबी का पता लगाना के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों और डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से टीबी के मामलों का सक्रियता से पता लगाया जाएगा। समुदाय की भागीदारी के लिए स्थानीय शहरी निकायों, जैसे नगर निगमों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा ताकि समुदाय स्तर पर टीबी नियंत्रण के प्रयासों को बढ़ाया जा सके। साथ ही, सभी संस्थाओं को जोड़ने के लिए मंत्रालय के सभी संगठन जैसे कि कार्यालय, सरकारी और स्वायत्त संस्थाएं और पीएसयू, टीबी जागरूकता और उन्मूलन की गतिविधियों में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयों में टीबी की रोकथाम, जाँच और इलाज के बारे में जानकारी देने वाले पोस्टर और सामग्री लगाई जाएगी। नगर निगम और नगर पालिकाओं जैसे शहरी निकायों द्वारा अपने क्षेत्रों में लगातार टीबी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी कर्मचारियों को टीबी के लक्षण, वह कैसे फैलता है।

और मुफ्त इलाज की सुविधाएं कहाँ उपलब्ध है, इसकी जानकारी दी जाएगी। मंत्रालय और उसके संस्थानों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर टीबी से जुड़े संदेश प्रसारित किए जाएंगे। मंत्रालय के सभी दफ्तरों में 'निक्षय मित्र' बनाए जाएंगे। ये निक्षय मित्र टीबी मरीजों को गोद लेंगे और उनके इलाज में मदद करेंगे। हरियाणा की यह पहल टीबी से लड़ने में हमारी मदद करेगी और हमें एक टीबी-मुक्त हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के करीब लाएगी।

पारिवारिक पेंशन मामलों में हरियाणा सरकार ने विभागों को दिए निर्देश

चंडीगढ़ ।

हरियाणा सरकार ने विधवा या तलाकशुदा बेटी और दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के मामलों में विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए, ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा विधवा या तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांग बच्चों के पेंशन मामले अक्सर नियमों के अनुरूप नहीं होते, जिससे दावेदार या आश्रित पारिवारिक सदस्य की आश्रितता तय करने में परेशानी आती है। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 8(10)(बी) में पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा स्पष्ट की गई है। इस नियम के नियम 8(10)(बी) के नीचे दिए गए नोट-3 में प्रावधान है कि वैध रूप से गोद लिया गया बेटा या बेटी कानूनी तौर पर दत्तक बच्चों में शामिल हैं, चाहे वे हिंदू कानून या किसी व्यक्तिगत विधि के तहत गोद लिए गए हों। यदि वे कर्मचारी के साथ रह रहे हैं और उस पर पूरी तरह से आश्रित हैं, तो वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हैं। हालांकि, सौतेले बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

दिल्ली को कूड़े से आजादी- सीएम रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लगाई झाड़ू

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया इस दौरान उन्होंने झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं उनके साथ अन्य नेता भी शामिल हुए। यह अभियान 1 से 31 अगस्त तक चल रहा है। जिसका उद्देश्य दिल्ली को कचरा-मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाना है।

आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे, सत्यपाल मलिक के निधन पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा- «पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा, जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे.» राहुल गांधी ने इस संदेश के जरिए सत्यपाल मलिक के परिवारजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 11 मई को भर्ती कराया गया था. वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली. सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे. उनके कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया. संयोगवश, उनकी मृत्यु उसी तारीख को हुई जब यह फैसला लिया गया था. पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा, जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे।

सभी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित करें : श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़ ।

- गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है -बजट में की गई विभागीय घोषणाओं की समीक्षा की

हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित करें, इसके अलावा यहां पर गोबर से ही पेंट बनाने तथा दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने की संभावनाओं की तलाश करें। इससे जहां गौशालाएं खर्च के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी वहीं लोगों को बेहतर गुणवत्ता के दुग्ध-उत्पाद मिल सकेंगे। श्री राणा आज यहां पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विनय दहिया, महानिदेशक डॉ. प्रेम सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे करनाल स्थित «नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टिट्यूट» के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करके इस इंस्टिट्यूट की आधुनिक तकनीकों को सीखें और प्रदेश के पशुओं की नस्ल सुधार और उनके दुग्ध उत्पादन आदि में प्रयोग करें। उन्होंने एनडीआरआई का अधिक से अधिक सदुपयोग करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। श्री श्याम सिंह राणा ने मार्च 2025 में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में की गई विभागीय घोषणाओं की समीक्षा की और इन सभी को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने, देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छंटाई के लिए प्रयोगशाला बनाने, गौ सेवा आयोग के तहत पंजीकृत गौशालाओं में शैड बनाने, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने, पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाई, ऊंत डाइग्नोस्टिक उपकरण लगाने जैसी घोषणाओं को भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जर्जर हालत के पशु चिकित्सा भवनों को जरुरत के अनुसार मरम्मत करने तथा नया भवन बनाने के भी निर्देश दिए।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की

उक्त बैठक के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा राज्य भण्डारण निगम से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की और निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम जल्द से जल्द बनाए जाएं। इस दौरान कोशिश करें कि गोदाम के पास ही अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो ताकि साथ में ही फसलों का खरीद केंद्र बनाया जा सके। इससे जहां फसल की ढुलाई का खर्च बचेगा वहीं अनाज मंडियों में भीड़ भी कम होगी। उन्होंने आधुनिक तकनीक का एक लाख टन क्षमता का प्रस्तावित साइलो तथा हिसार एयरपोर्ट पर बनने वाले गोदाम के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बैठक में हरियाणा राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन भी उपस्थित थे।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को पूरा करना सुनिश्चित करे अधिकारी : डीसी

पानीपत।

जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का शिवाजी स्टेडियम में होगा आयोजन।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने दिए दिशा निर्देश।

13 अगस्त को होगी फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल।

उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने मंगलवार को जिला सचिवालय के मीटिंग हाल में 79 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह तैयारियां पूरी करने के लिए अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए जिस भी विभाग को जो दायित्व दिया जाए उसे निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह शिवाजी स्टेडियम में मनाया जाएगा। उन्होंने क्रमवार विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिम्मेवारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि रिहर्सल और परेड के दौरान एंबुलेंस की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा और साफ-सफाई की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। वे इस बारे में पूरा ध्यान रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी निष्ठा के साथ पूरी करें। स्वतंत्रता दिवस की फाइनल फुल ड्रैस रिहर्सल 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपस में तालमेल बनाकर राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित करें। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पार्किंग, परेड की सलामी, मार्च पास्ट के लिए पुलिस विभाग और इसके लिए रिहर्सल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिला शिक्षा विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ पंकज यादव, एसडीएम पानीपत मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार एसडीएम इसराना नवदीप सिंह, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीएसपी सतीश बल्स सहित सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।

झुग्गी विरोधी BJP के खिलाफ़ कांग्रेस का विधानसभा घेराव

नई दिल्ली (ए के चौधरी) दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस के साथियों ने विरोध प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव किया।इस प्रदर्शन में दिल्ली प्रभारी में काजी निजामुद्दीन, पूर्व सांसद रमेश कुमार, संदीप दीक्षित, उदित राज, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डॉ नरेंद्र नाथ, डॉ. किरण वालिया जी, कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन अनिल भरद्वाज, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, अध्यक्ष, अलका लम्बा, अनुसूचित जाति विभाग चेयरमैन राजेंद्र गौतम पूर्व विधायक हरि शंकर गुप्त, भीष्म शुक्ला, जिलाध्यक्ष, हरिशंकर गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह व विजय कुमार भारती, महासचिव किराड़ी जिला सहित कांग्रेस के नेतागणों ने भाजपा की झुग्गी और गरीब विरोधी मानसिकता का पुरजोर विरोध किया। छाया- माहिल गौड

धर्मांतरण पर कड़ी निगरानी: अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को धर्मांतरण नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम, 2022 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित उपायुक्त को प्रपत्र क में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में धर्मांतरण किया जाने वाला युवा नाबालिग है, वहाँ माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को प्रपत्र ख में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, किसी भी धार्मिक पुजारी या धर्मांतरण समारोह का आयोजन करने वाले व्यक्ति को उस जिले के उपायुक्त को प्रपत्र ग में पूर्व सूचना देनी होगी जहाँ धर्मांतरण की योजना है। ऐसी घोषणाएँ या सूचनाएँ प्राप्त होने पर, उपायुक्त एक रसीद जारी करके उनकी पावती देंगे, जिससे धर्मांतरण प्रक्रिया का औपचारिक दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, अधिनियम में यह प्रावधान है कि सूचना प्रदर्शित होने के तीस दिनों के भीतर, कोई भी व्यक्ति उपायुक्त के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसी आपत्तियाँ प्राप्त होने

पर, उपायुक्त को निर्धारित अनुसार यहन सत्यापन और जाँच करने का अधिकार है। यदि जाँच के बाद, उपायुक्त पाते हैं कि प्रस्तावित धर्मांतरण अधिनियम का उल्लंघन है, जैसे कि बल प्रयोग, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अन्य निषिद्ध साधनों का प्रयोग, तो जिला उपायुक्त को एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश जारी करके धर्मांतरण की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को धोखे, जबरदस्ती या गैरकानूनी प्रलोभन से बचाना है। उन्होंने आगे बताया कि अधिनियम किसी भी व्यक्ति को गलत बयानी, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों (डिजिटल माध्यमों सहित) के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने या ऐसा करने का प्रयास करने से रोकता है। यह विवाह द्वारा या विवाह के लिए धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। प्रवक्ता ने बताया कि गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए एक से पाँच साल की कैद और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति शादी करने के लिए अपना धर्म छिपाता है, तो उसे तीन से दस साल की कैद और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का धर्मांतरण करने पर चार से दस साल की कैद और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण, जिसे एक ही समय में दो से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है, के लिए पाँच से दस साल की कैद और कम से कम चार लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि शादी के लिए अपना धर्म छिपाने के प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया कोई भी विवाह अमान्य माना जाएगा। हालाँकि, प्रवक्ता ने आगे बताया कि ऐसे विवाह से पैदा हुआ कोई भी बच्चा वैध माना जाएगा और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसके माता-पिता के उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार होगा।

बुढवा मंगल पर जिलाधिकारी ने किया अजोसी महावीर धाम में दर्शन-पूजन

जौनपुर ।

बुढवा मंगल पर्व के पावन अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने शक्ति पीठ मन्दिर अजोसी महावीर धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर की ऐतिहासिकता व पौराणिकता के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह मंदिर आस्था का प्रमुख केन्द्र है, जहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में फल भी वितरित किए। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह, प्रदीप सिंह सहित अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।

रक्षाबंधन पर महिला सशक्तिकरण और कृषि नवाचार की साझा झलक, देवरिया में कृषि मंत्री ने किया संयुक्त मेले का उद्घाटन

देवरिया।

रक्षाबंधन की सांस्कृतिक भावना और आधुनिक कृषि की वैज्ञानिक सोच को एक मंच पर समेटता हुआ संयुक्त रक्षाबंधन एवं कृषि मेला मंगलवार को देवरिया क्लब परिसर में भव्यता के साथ आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने मेले का शुभारंभ करते हुए नारी शक्ति और किसान हित को समाज की रीढ़ बताया। तीन दिनों तक चलने वाले रक्षाबंधन मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई रंग-बिरंगी राखियाँ, घरेलू सजावटी वस्तुएँ, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजन विशेष आकर्षण का केंद्र बने। महिलाओं ने मंत्री जी को राखी बांधकर रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई दी, वहीं मंत्री ने उनके आत्मनिर्भर प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे उत्पाद भी खरीदे। मंच से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिससे आत्मबल और स्वाभिमान का भाव मुखर रूप में दिखाई दिया। मेला परिसर में गर्भवती

महिलाओं को पोषण किट प्रदान की गई और छह माह पूरे कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी सादगी के साथ संपन्न हुआ। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खुद बच्चों को खीर खिलाकर इस आयोजन को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा और कहा कि रक्षाबंधन केवल रक्षा का व्रत नहीं, यह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। उसी दिन संपन्न कृषि मेला एवं गोष्ठी में किसानों के लिए एक दिवसीय तकनीकी संवाद आयोजित किया गया, जिसमें आधुनिक यंत्रीकरण, जैविक खेती, श्री अन्न (मिलेट्स), फसल अवशेष प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या की प्रो. डॉ. साधना सिंह ने पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिलेट्स की उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को सरकारी योजनाओं व वैज्ञानिक खेती के लाभों से अवगत कराया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किसानों को नवाचार अपनाने और कृषि के हर पहलू में आत्मनिर्भर बनने

मेले में आत्मनिर्भरता का संकल्प, मंत्री शाही बोले ङ्क अब राखी भी बनेगी लोकल टू ग्लोबल

का आह्वान किया। उन्होंने मेला परिसर में लगी सभी स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं और किसानों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम के अंत में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपस्थित जनसमूह को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पं. गिरीश चंद्र तिवारी, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन मिश्र, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उषा पासवान, जिला महामंत्री श्रीनिवास मणि, प्रमोद शाही, राजेश मिश्रा समेत जिले के गणमान्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, प्रगतिशील किसान व भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया।

उन्होंने दोपहर 1:12 बजे अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे जम्मू-कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। सत्यपाल 23 अगस्त

बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, उनके कार्यकाल में आज ही के दिन आर्टिकल-370 हटा था

2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सीबीआई ने 22 मई को सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें करीब 2,200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी।

जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय- प्रियंका

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं. इसे लेकर अब उनकी बहन प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता है कि सच्चा भारतीय कौन है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि वो यह तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है. सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है. मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ

नहीं बोलेगा, वह उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है. इसका गलत मतलब निकाला गया है. राहुल गांधी की सेना पर दिए गए बयानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था. साथ ही बाकी मामले भी लंबित थे, जिन्हें लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने राहुल गांधी से काफी तल्ख लहजे में सवाल किए, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आपको ये कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है. आपने बिना किसी सबूत के ऐसा बयान क्यों दिया? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे. कोर्ट ने राहुल से ऐसे मुद्दे संसद में उठाने के लिए भी कहा और पूछा कि ये सब सोशल मीडिया पर क्यों लिखते हैं?

कांग्रेस की सफाई, भाजपा का हमला

कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया। वे केवल सरकार से जवाब मांग रहे थे कि गलवां में चीन के हाथों हमारे जवानों की शहादत के बाद क्या कदम उठाए गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर चीन के समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रवैया देश विरोधी है। भाजपा नेताओं ने राहुल के पुराने बयानों को आधार बनाकर यह आरोप लगाया।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा, राज्यसभा में प्रस्ताव पास

नई दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया। यह अवधि 13 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इससे पहले 30 जुलाई को लोकसभा इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। गृह राय मंत्री नित्यानंद राय ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे भारी विपक्षी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था, जब मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था। जातीय टकराव और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है।

पुलिस नहीं रोक सकती पीडीए पाठशाला, अखिलेश बोले- सीएम खुद आकर हालात देखें

लखनऊ।

पीडीए पाठशाला को लेकर उठे विवाद के बीच, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि पुलिस पाठशाला को नहीं रोक सकती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें शामिल होकर हालात देखने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए, यादव ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी पार्टी तब तक छात्रों को पढ़ाना जारी रखेगी जब तक राय सरकार द्वारा बंद या विलय किए गए स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री को स्वयं पाठशाला में शामिल होकर हालात देखने चाहिए। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं और कुछ का विलय भी किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक छात्रों को पढ़ाते रहेंगे जब तक उन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती। इससे पहले, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा की पीडीए पाठशाला में पढ़ाए जा रहे पाठों को लेकर उस पर कड़ा प्रहार किया और उस पर भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह पार्टी की बुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। चौधरी ने एएनआई से कहा, जब सपा सत्ता में थी, तब उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की और आज भी कर रहे हैं। अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, सपा बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाने की हद तक जा सकती है। उनका स्कूल केवल भाई-भतीजावाद के बारे में है। वे अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ सकते।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए साधा निशाना

विदेशी हाथों में जाने वाले मुनाफे का आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए होता है इस्तेमाल

अलीगढ़।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को दावा किया कि दूसरे देशों में निर्मित सामान खरीदने पर 'विदेशी हाथों में जाने वाले मुनाफे का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद फैलाने के लिए किया जाता है। अलीगढ़ में 958 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का पुरजोर आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमारा पैसा अगर हमारे ही कारीगरों और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा तो यह विकास और समृद्धि का आधार बनेगा, लेकिन अगर हमारा ही पैसा विदेशी हाथों में जाएगा तो याद रखना, वह मुनाफा आतंकवाद के रूप में,

धर्मांतरण के रूप में, विस्फोट के रूप में भारत को अस्थिर करने के लिए भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए स्वदेशी आज की आवश्यकता है।

अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत दो अगस्त को वाराणसी में स्वदेशी अपनाने के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। आदित्यनाथ ने कहा, याद रखना, वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व और त्यौहार आता था तो उससे पहले प्रदेश में चीन के सामान लद जाया करते थे लेकिन 2018 के बाद जब 'एक जिला-एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया तो हमारे कारीगरों ने बाजार की मांग के अनुसार आइटम बनाने शुरू किये। उन्होंने किसी देश का नाम लिये बगैर कहा, मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को यह पैसा उपलब्ध करवा कर हमारा ही पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, इसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है और उसके बाद भी लगातार देख रहे हैं। योगी ने कहा, ''इसलिए प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे दैनिक जीवन हो या पर्व अथवा त्यौहार हो, हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वदेशी कभी देश के अंदर भारत की स्वाधीनता का आधार बना था। स्वदेशी को लेकर कभी लोगों ने बापू (महात्मा गांधी) के सपने को साकार करने के लिए उनके आह्वान पर देश के अंदर अलग-अलग आंदोलन प्रारंभ किए थे। आज हमारी आवश्यकता है कि हम नौ अगस्त को रक्षाबंधन, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और उसके बाद दो अक्टूबर को विजयादशमी और फिर दीपावली व अन्य त्यौहारों पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं।

हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच पिछली बैठक से एक कदम आगे बढकर सकारात्मक माहौल में हुई चर्चा - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ ।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में आज श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हरियाणा एवं पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ पानी के मुद्दे को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह काफी लम्बे समय से चला आ रहा विषय है। इसको लेकर 9 जुलाई को भी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें

काफी सकारात्मक चर्चा हुई। इस बार भी एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि 13

13 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में पॉजिटिव तरीके से दिया जाएगा जवाब - मुख्यमंत्री

अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया जाएगा।

हमें पूरा विश्वास है कि इस विषय का बेहतर हल निकलेगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इण्डस ट्रीटी सैक्रेण्डरी विषय है जिसमें राजस्थान को भी पानी मिलेगा। बैठक में केन्द्रीय सचिव देबाश्री मुखर्जी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बिहार में फिजिकल टीचरों की सैलरी हुई डबल, रसोइयों और रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ा, नीतीश कैबिनेट में 36 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16000 कर दिया गया है। वहीं रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय भी बढ़ाया गया है। बैठक के दौरान औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाने के फैसले पर मुहर लगी है। कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय में 712 पदों की स्वीकृति दी गई है जबकि, संख्या की संगणक के 534 पर कृषि संख्या की अनुदेशक की 178 पदों

की मंजूरी दी। कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 करने के प्रस्ताव को नीति सरकार ने मोहर लगा दिया है। इसके अलावा रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। रसोईया को अब प्रति माह 3 हजार 300 रुपये देने पर भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। वहीं बिहार राज विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूर कर लिया गया है। विराज के सरकारी गैर सरकारी सहायता अनुदित अल्पसंख्यक सहित मद उच्च विद्यालय में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक अकादमियों के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्त की दंड को बरकरा रखा गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तहत एक ऐप भी बनाई जाएगी- अनिल विज

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आने वाली 15 अगस्त तक बसों की ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में एक ऐप भी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से कोई भी यात्री यह देख सकें कि उसकी बस कितने बजे आ रही है। इसके अलावा, रोडवेज में उपकरणों/सामान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। श्री विज आज यहां चण्डीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे

थे। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री बनते ही आदेश दिए थे कि हरियाणा की सारी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डों पर भी बसों के आने-जाने की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए स्क्रीनें लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में रोडवेज के उपकरणों को खरीदने के लिए प्रस्ताव भेज जा चुका है और जल्द ही यह उपकरण व सामान आ जाएगा। इस संबंध में उनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि सामान का डिजिटल खाता रखा जाए कि किस गाड़ी में कब टायर डाला गया, कितने किलोमीटर गाड़ी चली और कब उस गाड़ी का टायर खराब हुआ है।